



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

उत्तर-दक्षिण कार्बन बाजार सहयोग की
शुरुआत

उत्तर-दक्षिण कार्बन बाजार सहयोग की शुरुआत

संदर्भ

- हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने एक नया रणनीतिक EU-भारत एजेंडा घोषित किया, जिसमें भारत के कार्बन बाजार को EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को शामिल किया गया है। यह वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच कार्बन बाजार तंत्र को संरेखित करने की दिशा में एक कदम है।

भारत का कार्बन बाजार (ICM)

- यह भारत को उसके जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है — विशेष रूप से 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 45% तक कम करने के लक्ष्य को।
 - इसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा बनाना है, जहाँ संस्थाएं अपने उत्सर्जन प्रदर्शन के आधार पर कार्बन क्रेडिट खरीद और बेच सकें।
 - इसकी कार्यप्रणाली में कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम, स्वैच्छिक और अनुपालन बाजार, तथा कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र शामिल हैं।

EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)

- इसका उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना है — जहाँ कंपनियाँ ढीले जलवायु नियमों वाले देशों में उत्पादन स्थानांतरित कर देती हैं।
- यह सुनिश्चित करता है कि आयातित वस्तुओं पर वही कार्बन लागत लागू हो जो EU के अंदर उत्पादित वस्तुओं पर होती है, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर समान होता है और वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन को प्रोत्साहन मिलता है।
- इसकी कार्यप्रणाली में आयात पर कार्बन मूल्य निर्धारण और सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्युमिनियम, उर्वरक, विद्युत एवं हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

भारत के ICM और EU के CBAM को जोड़ना: नया रणनीतिक EU-भारत एजेंडा

- इसका उद्देश्य सीमाओं के पार कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र को संरेखित करना है, ताकि भारतीय निर्यातकों को EU के जलवायु नियमों के अंतर्गत अनुचित दंड का सामना न करना पड़े।
- यह पाँच प्रमुख स्तंभों को रेखांकित करता है:
 - समृद्धि एवं स्थिरता;
 - प्रौद्योगिकी एवं नवाचार;
 - सुरक्षा एवं रक्षा;
 - संपर्क एवं वैश्विक मुद्दे; और
 - स्तंभों के बीच सहायक तत्व।
- क्या प्रस्तावित किया जा रहा है?
 - भारत के कार्बन क्रेडिट की मान्यता:** EU भारतीय निर्यातकों को भारत के घरेलू कार्बन बाजार से खरीदे गए कार्बन क्रेडिट का उपयोग करके अपनी CBAM देनदारियों को समायोजित करने की अनुमति दे सकता है।
 - दोहरी कार्बन कराधान से बचाव:** इससे भारतीय उद्योगों को घरेलू कार्बन मूल्य और EU को CBAM शुल्क दोनों का भुगतान करने से राहत मिल सकती है।

- **MRV प्रणालियों में आपसी विश्वास:** इस एकीकरण के लिए दोनों पक्षों को निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) मानकों पर सहमति बनानी होगी ताकि पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

प्रस्तावित एकीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ

- **भारत का अविकसित कार्बन बाजार:** भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), जिसे सामान्यतः ICM कहा जाता है, अभी प्रारंभिक अवस्था में है।
 - इसके विपरीत, EU की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) एक परिपक्व बाजार है जिसमें स्पष्ट सीमा, सत्यापन और प्रवर्तन तंत्र हैं, जबकि भारत की योजना तीव्रता-आधारित सुधारों और परियोजना-स्तरीय ऑफसेट्स पर निर्भर करती है, न कि पूर्ण उत्सर्जन सीमा पर।
- **संस्थागत समानता की कमी:** EU की ETS स्वतंत्र नियामकों और सत्यापित रजिस्ट्रियों के अंतर्गत संचालित होती है, जो अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
 - भारत में वर्तमान में ऐसे समकक्ष संस्थान नहीं हैं, जिससे EU अधिकारियों को भारतीय क्रेडिट को CBAM कटौती के लिए मान्य मानने में संकोच होता है।
- **मूल्य अंतर की समस्या:** EU की ETS के अंतर्गत कार्बन मूल्य €60–€80 प्रति टन के बीच है, जबकि भारत में यह €5–€10 प्रति टन के बीच है।
 - तुलनीय और प्रवर्तनीय कार्बन मूल्य के बिना, EU सार्थक कटौती देने की संभावना नहीं रखता, जिससे भारतीय निर्यातिक घरेलू अनुपालन लागत एवं CBAM शुल्क दोनों के भार में फँस सकते हैं।
 - इससे भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया और औद्योगिक विरोध उत्पन्न हो सकता है, जो इसके कार्बन तंत्र की विश्वसनीयता को कमज़ोर कर सकता है।
- **CBAM की राजनीतिक और कानूनी विसंगतियाँ:** तकनीकी पहलुओं से परे, CBAM की एकतरफा प्रकृति इसे विवादास्पद बनाती है।
 - भारत एवं कई विकासशील देशों ने WTO में CBAM की आलोचना की है तथा इसे संरक्षणवादी और भेदभावपूर्ण बताया है।
 - ICM को CBAM से जोड़ने से भारत उस प्रणाली को वैधता दे सकता है जिसका वह वैश्विक मंचों पर विरोध करता रहा है।
- **संप्रभुता और विश्वास के मुद्दे:** EU द्वारा यह तय करना कि भारत का कार्बन मूल्य ‘पर्याप्त’ है या नहीं, संप्रभुता से जुड़ी चिंताओं को जन्म देता है।
 - यदि EU पूर्ण कटौती से मना करता है, तो भारत को राजनीतिक विवादों या कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आ सकता है।
 - इसके अतिरिक्त, यदि भारत में राजनीतिक या औद्योगिक दबाव के कारण कार्बन अनुपालन में कोई घरेलू कमी आती है, तो निर्यातिकों को तुरंत अधिक CBAM लागत का सामना करना पड़ सकता है — जिससे यह एकीकरण संवेदनशील और आपसी विश्वास पर निर्भर हो जाता है।

वास्तविक साझेदारी के मार्ग

- प्रस्तावित एकीकरण, जोखिमों के बावजूद, कार्बन बाजारों में उत्तर-दक्षिण सहयोग के लिए एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। इस एकीकरण की सफलता के लिए:

- भारत को अपने कार्बन बाजार ढांचे को सुदृढ़ सीमा, सत्यापन योग्य लेखांकन और नियामक स्वतंत्रता के साथ सुदृढ़ करना होगा।
- EU को भारत के बाजार परिपक्वता में सहयोग के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- दोनों पक्षों को एक यथार्थवादी कार्बन मूल्य न्यूनतम तय करना चाहिए और पारदर्शी सत्यापन तंत्र बनाना चाहिए ताकि विश्वास स्थापित हो सके।

निष्कर्ष: वादे से क्रियान्वयन तक

- ICM-CBAM एकीकरण वैश्विक कार्बन शासन को पुनर्परिभाषित कर सकता है, व्यापार और जलवायु लक्ष्यों को दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सेरेखित कर सकता है।
- लेकिन यदि विश्वसनीय सुधार, मूल्य संरेखण और निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होती, तो यह समझौता केवल कागजी सफलता बनकर रह सकता है।
- इसे वास्तविकता में बदलने के लिए अर्थशास्त्र, कूटनीति और विश्वास के संवेदनशील संतुलन की आवश्यकता होगी — जो नए EU-भारत रणनीतिक एजेंडा की वास्तविक परीक्षा होगी।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: जलवायु समानता और वैश्विक व्यापार निष्पक्षता को बढ़ावा देने में भारत के कार्बन बाजार (ICM) को यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) से जोड़ने के महत्व पर चर्चा कीजिए। इस सहयोग में कौन सी चुनौतियाँ बाधा बन सकती हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है?

